

लंबित मामलों की चिंता

देश की अदालतों में करीब 5 करोड़ लंबित मामले पड़े हैं। अगर कोई जज 50 मामलों का निपटारा करता है, तो 100 नए मुकदमों दायर कर दिए जाते हैं। क्योंकि लोग अब अधिक जागरूक हैं और विवादों को निपटाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ससत्र बल न्यायाधिकरण के कामकाज पर एक सेमिनार में रिजिजू ने कहा कि सरकार अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ मध्यस्थता पर प्रस्तावित कानून अदालतों में मुकदमों की संख्या को कम करने में मदद करेगा। रिजिजू ने यह भी कहा कि दूसरे देशों में लंबित मामलों के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ मध्यस्थता पर प्रस्तावित कानून अदालतों में मुकदमों की संख्या को कम करने में मदद करेगा। रिजिजू ने यह भी कहा कि दूसरे देशों में लंबित मामलों के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ मध्यस्थता पर प्रस्तावित कानून अदालतों में मुकदमों की संख्या को कम करने में मदद करेगा। रिजिजू ने यह भी कहा कि दूसरे देशों में लंबित मामलों के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है।

बढ़ती निर्धनता

वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारतीय परिवारों की औसत आय 2021-22 की पहली तिमाही से कम रहने का अनुमान है। हालांकि इसी तुलनात्मक आधार पर उपभोक्ता रुझान में कमी आयी है। साफ तौर पर परिवारों की अपनी आर्थिक सेहत को धारणा पर उससे कहीं अधिक चोट पड़ी है, जो उनकी आमदनी पर चोट पड़ी है। यह तुलना पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि रुझान की गणना में सभी परिवारों को समान माना जाता है, लेकिन परिवारिक आमदनी की गणना में सभी परिवार एकसमान नहीं हैं। समूह परिवारों का औसत में बड़ा हिस्सा है क्योंकि उनकी आमदनी गरीब परिवारों की तुलना में अधिक है। इसलिए अंतर का पता इन दो गणनाओं में निहित भ्रान्तों के अंतर से ज्ञात किया जा सकता है। अनुमानों की ऐसी उलझन वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही की पहली तिमाही से तुलना को जटिल नहीं बनाती है। दूसरी तिमाही में औसत परिवारिक आय पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 14 फीसदी कम थी। यह पहले तिमाही में दर्ज 33 फीसदी गिरावट की तुलना में काफी कम हुई है। हालांकि आमदनी में काफी सुधार हुआ है, लेकिन रुझान में इस अनुपात में सुधार नहीं आया। उपभोक्ता रुझान अब भी पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 57 फीसदी नीचे है। यह 'सुधार' महज दो फीसदी था, जो 59 फीसदी की गिरावट से 57 फीसदी की गिरावट पर आ गया है। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि आय में बढ़ोतरी के साथ रुझान अनुपातिक रूप में नहीं बढ़ता है। जब तक रुझान में सुधार नहीं आता है, तब तक मांग आय में सुधार के अनुपात में नहीं बढ़ेगी। शायद यह वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में जारी आधिकारिक राष्ट्रीय खातों के आंकड़ों में निजी अंतिम उपभोग व्यय में 2.4 फीसदी गिरावट का कारण बताया है।

सुलोचना का विश्वास

धर्म प्रवाह

स्वामी सत्यानंदजी सरस्वती

वानर सेना को रावण के आने से दुविधा हो गयी। उन्होंने राम से पूछा कि आपने विभीषण को लंकापति बनने का वचन दिया है। हमलोग उन्हें लंकेश कहते हैं। राम बोले आप लोग धवराइये नहीं। आप लोग धवराइये नहीं अंगर रावण वास्तव में हमारे पास शरणगत हो जाता है तो दुनिया में सबसे अधिक भरे लिये प्रिये हो जाएगा मैं उसे अवधेश बना दूंगा। अयोध्या की गद्दी में रावण को दे दूंगा। जब पालकी निकट आई उसमें से सुलोचना निकली। वह राम के सम्मुख गयी। हाथ जोड़कर परिचय दी। मैं रावण की पुत्रवधु और मेघनाथ की पत्नी हूँ। उसके आप भरे वचन एवं दुख को देखकर राम त्रित हो गये। उन्होंने कहा सुलोचना मैं तुम्हारे दुख से

दुखी हूँ। तुम्हारे पति की मृत्यु अवश्य हुई है लेकिन अगर मेरे सारे पुण्य लेने से तुम्हारे पति जीवित होते हैं तो तुम ले लो। मैं जीवन भर के पुण्य तुम्हें देने को तैयार हूँ। इससे अगर तुम्हारे पति जिंदा होत हैं तो मैं तैयार हूँ। सुलोचना बोली प्रभु जैसा सुनी थी वैया पायी लेकिन मेरे पति स्वर्ग की शोभा बड़ा रहे हैं मैं उन्हें धरती पर वापस नहीं लाना चाहती हूँ। मैं उनके मृतक शरीर को लेकर सती बनना चाहती हूँ इसलिये मेरे पति का सिर मुझे मिल जाए तो मैं वापस चला जाऊँ। राम ने आदेश दिया सती नारी को उसके पति का सिर सम्मान के साथ वापस किया जाए। वह सिर लेने के बाद बोली मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। आपको आर्शिवाद देकर जाती हूँ। संसार में सत्य की विजय होती है। (ब्रह्म विद्यालय सह आश्रम)



समाचार कर्तव्यकर्तव्य डॉक के बारे में लेटर टू एडिटर

भारत की छवि

रेवड़ी कल्चर के खतरे

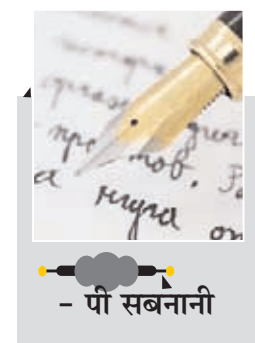
अमेरिका के पेंटागन ने हाल ही में कहा है कि अब भारत के अधिकारियों के अमेरिका आने-जाने पर कोई कागजी कार्रवाई या फिर कड़ी छानबीन नहीं की जाएगी। दरअसल इसकी घोषणा अमेरिका ने तब की जब भारत अपने आजादी के 78 साल होने पर आजादी का महोत्सव मना रहा है। ज्ञात ही कि अमेरिकाई दूत जहाँ अपने सबसे करीबी देशों को देता है।
—अनिल सिंह, रांची

भारत की पूर्वी राज राज मणिपुर, पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश की घटनायें एक-दूसरे से संबंधित हैं। यह सभी घटनायें एक बड़े षट्‌यंत्र का हिस्सा है। अमेरिकी सरकार ने बांग्लादेश के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया, लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव को बढ़ावा देने की आड़ में कई सारे प्रतिबंध लगाए। यह कार्रवाई बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने का एक रणनीतिक हिस्सा है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके पास बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक प्रमुख और खालिदा जिजा के बेटे तारिक रहमान और सऊदी अरब में आईएसआई अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख

विनिर्माण क्षेत्र और बदलते भारत की तस्वीर

भारत में आज भी देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास कर रही है और वह अपने रोजगार के लिए सामान्यतः कृषि क्षेत्र पर निर्भर है तथा देश की कुल अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 16-18 प्रतिशत के आसपास बना रहता है। अब यदि देश की 60 प्रतिशत आबादी देश के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 16-18 प्रतिशत तक का योगदान दे पा रही है तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में गरीबी तो बनी ही रहेगी। परंतु, यह स्थिति अब धीरे धीरे बदल रही है क्योंकि हाल ही के वर्षों में भारत के विनिर्माण क्षेत्र का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों के नागरिक शहरी क्षेत्रों में स्थापित की जा रही विनिर्माण इकाईयों में रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र में कई ऐसे नए क्षेत्र भी उभरकर सामने आए हैं जिन क्षेत्रों में भारत में उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता रहा है। उदाहरण के लिए रक्षा क्षेत्र, दवा क्षेत्र, सेमी-कंडक्टर निर्माण क्षेत्र एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र आदि का वर्णन यहां प्रमुख रूप से किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में स्वदेशी रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा 1.27 लाख करोड़ रुपये की रही है जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय 16.7 प्रतिशत अधिक है। यह भारत सरकार द्वारा देश में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों और सरकार के प्रयासों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। वर्तमान में रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन करने वाली इकाईयों में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त वर्णित उत्पादन में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का योगदान 79.2 प्रतिशत का रहा है जबकि निजी क्षेत्र की कम्पनियों का योगदान 20.8 प्रतिशत का रहा है। हर्ष का विषय तो यह भी है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत में निर्मित किए जा रहे उत्पादों की अन्य देशों में भारी मांग निर्मित होती जा रही है और इन उत्पादों का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात भारत से विभिन्न देशों में किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत अधिक है और यह भारत में रक्षा के



भारतीय दवा उद्योग के वर्ष 2024 के अंत तक 6,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2030 तक 13,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। वर्ष 2013-14 के बाद से वर्ष 2021-22 तक भारतीय दवा निर्यात में 103 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई है। जेनेरिक दवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत हो गई है, जिससे भारत को अब विश्व का फार्मेसी हब भी कहा जाने लगा है।

क्षेत्र में हुए कुल उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत है। भारत में विनिर्माण इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही के समय में कई रणनीतिक पहलू भी केंद्र सरकार द्वारा की गई हैं, जैसे, मजबूत नीतिगत ढांचे को विकसित करना, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं विकास कार्यों में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देना, आदि शामिल हैं। स्वदेशीकरण की नीति के अनुपालन का अक्षर भी रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन एवं निर्यात में हो रही भारी भरकम वृद्धि के रूप में दिखाई देने लगा है। रक्षा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले सैकड़ों उत्पादों के आयात पर रोक लगाकर इन उत्पादों का उत्पादन भारत में ही करने के निर्णय का असर

भी अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों का उत्पादन भारत में ही करने की नीति को लागू करने से देश में न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश में आर्थिक प्रगति, तकनीकी उन्नति एवं रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। कुछ वर्ष पूर्व तक दवा निर्माण के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले एपीआई (एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट) नामक कच्चे माल का लगभग पूरा तौर पर चीन से आयात किया जाता था। परंतु, कोरोना महामारी के दौरान भारत को यह अहसास हुआ कि यदि चीन इस कच्चे माल का निर्यात भारत को करना कम कर दे अथवा बंद कर दे तो भारत में तो दवा उद्योग की इकाईयों में निर्माण कार्य

सुलोचना का विश्वास

धर्म प्रवाह

स्वामी सत्यानंदजी सरस्वती

वानर सेना को रावण के आने से दुविधा हो गयी। उन्होंने राम से पूछा कि आपने विभीषण को लंकापति बनने का वचन दिया है। हमलोग उन्हें लंकेश कहते हैं। राम बोले आप लोग धवराइये नहीं। आप लोग धवराइये नहीं अंगर रावण वास्तव में हमारे पास शरणगत हो जाता है तो दुनिया में सबसे अधिक भरे लिये प्रिये हो जाएगा मैं उसे अवधेश बना दूंगा। अयोध्या की गद्दी में रावण को दे दूंगा। जब पालकी निकट आई उसमें से सुलोचना निकली। वह राम के सम्मुख गयी। हाथ जोड़कर परिचय दी। मैं रावण की पुत्रवधु और मेघनाथ की पत्नी हूँ। उसके आप भरे वचन एवं दुख को देखकर राम त्रित हो गये। उन्होंने कहा सुलोचना मैं तुम्हारे दुख से



समाचार कर्तव्यकर्तव्य डॉक के बारे में लेटर टू एडिटर

भारत की छवि

रेवड़ी कल्चर के खतरे

अमेरिका के पेंटागन ने हाल ही में कहा है कि अब भारत के अधिकारियों के अमेरिका आने-जाने पर कोई कागजी कार्रवाई या फिर कड़ी छानबीन नहीं की जाएगी। दरअसल इसकी घोषणा अमेरिका ने तब की जब भारत अपने आजादी के 78 साल होने पर आजादी का महोत्सव मना रहा है। ज्ञात ही कि अमेरिकाई दूत जहाँ अपने सबसे करीबी देशों को देता है।
—अनिल सिंह, रांची

भारत की पूर्वी राज राज मणिपुर, पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश की घटनायें एक-दूसरे से संबंधित हैं। यह सभी घटनायें एक बड़े षट्‌यंत्र का हिस्सा है। अमेरिकी सरकार ने बांग्लादेश के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया, लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव को बढ़ावा देने की आड़ में कई सारे प्रतिबंध लगाए। यह कार्रवाई बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने का एक रणनीतिक हिस्सा है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके पास बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक प्रमुख और खालिदा जिजा के बेटे तारिक रहमान और सऊदी अरब में आईएसआई अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख

अंतःकरण-पावित्र्य, आत्म-विश्वास और आशावादिता जीवन की महत्तम विभूति हैं ! जीवन अंतहीन संभावनाओं और अवसरों का अखंड स्रोत है ! आध्यात्मिक व्यक्ति प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूलता और उचित अवसर ढूँढ लेता है।

- स्वामी अवधेशानंद गिरि

रोचक

ट्वीट

झारखण्ड में हमने पिछले 24 सालों में कई सरकारों देखी हैं, पर हमारी बहन-बेटियों के उथान और उन्हें सशक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का संकल्प सिर्फ हमारी सरकार ने दृढ़ता से निभाया है।

- हेमंत सोरेन, सीएम

जब भूजल विषाक्त हो जाएगा तब क्या होगा ?

एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने वैश्विक तापमान वृद्धि के विभिन्न परिदृश्यों के तहत दुनिया भर में भूजल स्रोतों के तापमान परिवर्तनों को सटीक संख्या में बनाने के लिए ऊष्मा परिवहन का एक विश्व-स्तरीय मॉडल विकसित किया है। इस समय गर्मी की लहरें, बर्फ की पिघलती हुई टोपियां और समुद्रों का बढ़ता स्तर नियमित रूप से सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान भूमि पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों की तरफ नहीं जाता।

हमें भूजल पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में अधिक व्यापक रूप से सोचने की आवश्यकता है। यह सच है कि हमारे पैरों के नीचे की चट्टान और मिट्टी की परतें समुद्री जल की गर्मी को अवशोषित करने की क्षमता से

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बड़ा खतरा बना बांग्लादेश

हसीना ने भी दावा किया था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काटकर एक नया ईसाई देश बनाने की साजिश रची जा रही है। अमेरिका उनसे एक हवाई पट्टी बनाने की मांग भी कर रहा था। अमेरिका ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी और उसके सहयोगी जमात-ए-इस्लामी को भी समर्थन दिया था। जमात-ए-इस्लामी, बांग्लादेश बनने के बाद से ही कई तरह की अस्थिर गतिविधियों में शामिल रहा है और कहीं न कहीं पाकिस्तान का समर्थक भी है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या अस्थिरता और अराजकता रही है। बांग्लादेश बनने के बाद से कभी भी सरकार पूर्ण मजबूती के साथ स्थिरता से नहीं चला पाई। मुजीबुर रहमान ने भारत के सहयोग से मुक्ति वाहिनी बनाई और बांग्लादेश का गठन किया। परंतु सेना में सत्ता पर कब्जा कर लिया। इरशाद को हटाने के लिए हसीना और जिया देवों से आर्सेनिक और मैगनीज जैसी भारी धातुओं की अत्यधिक मात्रा पानी में घुल सकती है। अक्षर्यजनक है कि भूजल के गर्म होने के परिणामों पर इतना कम ध्यान दिया गया है, खासकर जब पानी की कमी और रिकार्ज (पुनर्भरण) दर पर इतनी अधिक चर्चा होती है। सतह के ठीक नीचे छिद्रपूर्ण चट्टानों के भीतर फंसा पानी घुले हुए खनिजों, प्रदूषकों और संभावित रोगजनकों से भरा हो सकता है। बहुत बड़ी आबादी के समक्ष इस प्रदूषित जल पर निर्भर रहने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। इन भूमिगत जलाशयों को सिर्फ एक या दो डिग्री गर्म करने से परिणाम भयावह हो सकते हैं। इससे पर्वतारोहण में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और खतरनाक बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा मिल सकता है, या आर्सेनिक और मैगनीज जैसी भारी धातुओं की अत्यधिक मात्रा पानी में घुल सकती है।

दुनिया में पहले से ही लगभग तीन करोड़ लोग ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहां रिकार्ज (पुनर्भरण) दर पर इतनी अधिक चर्चा होती है। सतह के ठीक नीचे छिद्रपूर्ण चट्टानों के भीतर फंसा पानी घुले हुए खनिजों, प्रदूषकों और संभावित रोगजनकों से भरा हो सकता है। बहुत बड़ी आबादी के समक्ष इस प्रदूषित जल पर निर्भर रहने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। इन भूमिगत जलाशयों को सिर्फ एक या दो डिग्री गर्म करने से परिणाम भयावह हो सकते हैं। इससे पर्वतारोहण में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और खतरनाक बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा मिल सकता है, या आर्सेनिक और मैगनीज जैसी भारी धातुओं की अत्यधिक मात्रा पानी में घुल सकती है।

दुनिया में पहले से ही लगभग तीन करोड़ लोग ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहां रिकार्ज (पुनर्भरण) दर पर इतनी अधिक चर्चा होती है। सतह के ठीक नीचे छिद्रपूर्ण चट्टानों के भीतर फंसा पानी घुले हुए खनिजों, प्रदूषकों और संभावित रोगजनकों से भरा हो सकता है। बहुत बड़ी आबादी के समक्ष इस प्रदूषित जल पर निर्भर रहने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। इन भूमिगत जलाशयों को सिर्फ एक या दो डिग्री गर्म करने से परिणाम भयावह हो सकते हैं। इससे पर्वतारोहण में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और खतरनाक बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा मिल सकता है, या आर्सेनिक और मैगनीज जैसी भारी धातुओं की अत्यधिक मात्रा पानी में घुल सकती है।



वैज्ञानिक प्रगति से ही विश्व में बने कई आधुनिक उपकरण: एसडीपीओ

सांता पब्लिक स्कूल गुमला में साइंस एग्जीबिशन का किया गया आयोजन

खबर मन्त्र संवाददाता

गुमला। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने कहा है कि आधुनिक युग को विज्ञान के युग के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण ही आज विश्व में कई ऐसे उपकरण बन पाए हैं। जिससे सभी देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। श्री यादव ने गुरुवार को सांता पब्लिक स्कूल गुमला में आयोजित साइंस एग्जीबिशन कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों की प्रतिभा को निखार जा सकता है। सांता पब्लिक स्कूल का प्रयास सहाहक है। वहीं विशिष्ट अतिथि डालसा के सदस्य शंभू सिंह ने कहा कि सांता पब्लिक स्कूल में प्री एडमिशन



करना तारीफ के काबिल है। आज का विज्ञान प्रदर्शनी निश्चित ही तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करती है। वहीं लायंस क्लब गुमला ग्रेटर के अध्यक्ष राजेश लोहानी और स्कूल के संरक्षक शंकर लाल

जाजोदिया ने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम से बच्चों में मानसिक तथा बौद्धिक विकास होता है और बच्चों कुछ नया करने को प्रोत्साहित होते हैं। स्कूल के डायरेक्टर हेमंत कुमार कुमारी, जसिंता बेक, नेहा, सीमा, सुनीता, मुक्कान, अंजनी, नोबेर्ट बेक, आदि सहित स्कूल के टीचर्स और परेंट्स उपस्थित थे।

जाजोदिया ने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम से बच्चों में मानसिक तथा बौद्धिक विकास होता है और बच्चों कुछ नया करने को प्रोत्साहित होते हैं। स्कूल के डायरेक्टर हेमंत कुमार कुमारी, जसिंता बेक, नेहा, सीमा, सुनीता, मुक्कान, अंजनी, नोबेर्ट बेक, आदि सहित स्कूल के टीचर्स और परेंट्स उपस्थित थे।

सिपाही बहाली को लेकर दौड़ का अभ्यास कर रही युवती ट्रक के धक्के से घायल

- विरोध में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, बाँक्साइट ट्रकों को तेज गति चलाने पर अंकुश लगाने की मांग

खबर मन्त्र संवाददाता

घाघरा। घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी के समीप गुरुवार की सुबह सिपाही बहाली की तैयारी के लिए दौड़ का अभ्यास कर रही युवती पूर्णिमा कुमारी बाँक्साइट ट्रक के धक्के से घायल गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से 108 एंबुलेंस की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा लाया गया। जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक



उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु युवती को गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं गुस्ताफ ग्रामीणों और परिजन ने देवाकी के समीप सड़क जाम कर दिया। जिससे बाँक्साइट व अन्य वाहन खड़ी रही। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पहुंच लोगों को समझाया। लेकिन परिजन ट्रक

मालिक को बुलाने पर अड़े रहे। इसके बाद लगभग 9:00 बजे ट्रक मालिक घटनास्थल पहुंचा। जहाँ घायल के इलाज की मदद की बात परिजनों द्वारा कही गई। वहीं पुलिस के दुबारा समझाने के बाद जाम हटा लिया गया। परिजनों ने बताया कि उत्पाद विभाग में सिपाही का वैकेंसी निकला है। जिसे लेकर

प्रत्येक दिन पूर्णिमा द्वारा अभ्यास दौड़ का किया जा रहा था। जहां आज प्रातः भी वह दौड़ रही थी। जहां बाँक्साइट ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे वह घायल हो गई। लगातार बाँक्साइट ट्रक तेज गति से अपने वाहनों को चलाते हैं जिस पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

मंत्री प्रतिनिधि बनाकर वित्त मंत्री ने की अच्छी शुरुआत : रोहित उरांव

- मंत्री प्रतिनिधि का विरोध सांसद सुखदेव भगत का निजी विचार : हाजी अफसर कुरेशी

खबर मन्त्र संवाददाता

लोहरदगा। लोहरदगा से विधायक और राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव द्वारा हाजी अफसर कुरेशी को मंत्री प्रतिनिधि बनाए जाने पर लोहरदगा से कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने सवाल खड़े करते हुए नाराजगी जताई थी। सुखदेव भगत ने इसे असंवैधानिक बताया हए वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव पर निशाना साधा था। वहीं अब वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव



के नवनियुक्त मंत्री प्रतिनिधि हाजी अफसर कुरेशी और वित्त मंत्री के पुत्र समाजसेवी रोहित उरांव ने पलटवार किया है। गुरुवार को हाजी अफसर कुरेशी के आवास पहुंचे मंत्री पुत्र रोहित उरांव मंत्री प्रतिनिधि नियुक्ति को जायज ठहराते हुए कहा कि उनके पिताजी वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने राज्य में देर से ही लेकिन एक अच्छी परंपरा का शुरुवात किया है।

राज्य में नए चलन का शुरुवात हुआ है सबको इसका स्वागत करना चाहिए। वित्त मंत्री कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि सांसद सुखदेव भगत विरोध कर रहे हैं वह उनका निजी निर्णय है। वहीं नवनियुक्त मंत्री प्रतिनिधि हाजी अफसर कुरेशी ने वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव का आभार व्यक्त करते हुए कहा

वित्त मंत्री अल्पसंख्यक के चहेते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सभी समुदाय का है और इस पार्टी में सबको अधिकार मिले इसी सोच के साथ मुझे प्रतिनिधि बनाया गया है। सांसद और कुछ कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं वो उनके निजी विचार हैं। मैं शुरू से कांग्रेसी रहा हूँ और कांग्रेस के लिए काम करते आया हूँ। इस मौके पर जमील अंसारी, हाजी शमशेर कुरेशी, इश्माद आलम, रबिल खान, जिकू कुरेशी, जाफर इमामा, रिंकू कुरेशी, एमडी दानिश, रैनक इकबाल, टिंकू कुरेशी, रिंकू कुरेशी, असफ अंसारी, मो.साजिद, तनवीर अंसारी, जफर आलम आदि मौजूद थे।

एटीएस ने कुड़ू में की छापेमारी, दो देसी हथियार बरामद

- छापेमारी में आतंकी साहित्य सहित कई कई आपत्ति जनक सामान भी बरामद

खबर मन्त्र संवाददाता

लोहरदगा। जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र में आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने कुड़ू के कौवाखाप गांव से आतंकी संगठन से जुड़े अलताफ अंसारी के घर पर छापेमारी कर हथियार सहित कई आपत्ति जनक सामग्री बरामद की है। एटीएस की टीम ने अलताफ अंसारी के घर से दो कट्टरी मेड हथियार बरामद किया है। हालांकि आतंकी संगठन से जुड़े अलताफ अंसारी फरार है, जिसकी धड़ पकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। एटीएस की टीम ने राज्य के 14 जगहों पर छापेमारी कर



अलताफदा इंडियन सबकार्टिनेट (एक्यूआईएस) आतंकी संगठन के कई आतंकियों को पकड़ा है। एटीएस की टीम ने लोहरदगा के कुड़ू, हजारीबाग सहित अन्य कई जिलों में 14 जगहों पर छापेमारी कर आतंकियों को गिरफ्तार फरार है, जिसकी धड़ पकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। एटीएस की टीम ने राज्य के 14 जगहों पर छापेमारी कर

साहित्य आदि बरामद कर एटीएस की टीम अपने साथ ले गई। फरार आतंकी के परिवार से एटीएस ने पूछताछ किया है। उनकी योजना क्या थी, कब से और किसके संपर्क में थे, इसपर एटीएस के अधिकारी जानकारी ले रहे हैं। एटीएस को सूचना है कि अलताफदा इंडियन सब कार्टिनेट अंसारुल्लाह बाबला टीम के साथ इस्लामिक राज्य बनाने की फिराक में है। इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पूरे मामले की लोहरदगा एएसपी हारिस बिन जमा ने पुष्टि की है। एसपी ने कहा कि कुड़ू थाना क्षेत्र के कौवा खाप गांव में अलताफ अंसारी के घर पर एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। मौके से अलताफ फरार हो गया है। अलताफ के घर से कई देशी हथियार मिले हैं। मामले को लेकर छानबीन की जा रही है।

स्पीड न्यूज

बसिया प्रखंड परिसर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन

बसिया। प्रखंड परिसर बसिया में गुरुवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रखंड परिसर बसिया में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कई मूल्यवान एवम फलदार पौधे लगाए गए लीके पर बीडीओ सुप्रिया भगत सी ओ नरेश मुंडा के अलावे प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राए प्रखंड एवम अंचलकर्मी उपस्थित थे। इस अवसर पर बीडीओ सुप्रिया भगत ने कहा कि अगर धरती को बचाना है तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि एक पेड़ अवश्य लगाए और उसे संरक्षण देकर पेड़ का रूप दे दें। उन्होंने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की साथ ही अंचल अधिकारी नरेश मुंडा ने भी पौधरोपण किया। मौके पर बीटीएम रश्मि सुरीन विवाकर केशरी राजीव कंट सोनू ओहदार सुकरत उरांव रविन्द्र भगत सही कई लोग उपस्थित थे।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 26 को, भजन संध्या व झांकी का होगा मंचन

गुमला। रौनियार वेश्य समाज गुमला के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस निमित्त समाज के पदाधिकारियों की बैठक रौनियार धर्मशाला में संपन्न हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 26 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार रौनियार धर्मशाला परिसर में धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम में विनय मिश्रा एंड म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा भजन संध्या की प्रस्तुति की जाएगी। इसके अलावा कलाकारों द्वारा बृहत रूप से आकर्षक झांकी का मंचन किया जाएगा। समाज के अध्यक्ष विनोद प्रसाद और सचिव अनमोल गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम संध्या 7:00 बजे से आरंभ होगा। मंदिर परिसर में भव्य पंडाल का निर्माण होगा और आकर्षक रूप से श्रीराधा कृष्ण मंदिर को सजाया जाएगा। मौके पर समाज के कई पदाधिकारी मौजूद थे।

शास्त्री नगर में एसडीपीओ ने की मुहल्ले के लोगों की सुरक्षा को लेकर बैठक

गुमला। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश प्रसाद यादव की अध्यक्षता में टोटो बीट अंतर्गत शास्त्री नगर में पुलिस नागरिक सुरक्षा समिति तथा सुरक्षा आजीविका महिला समिति के सदस्यों की बैठक हुई। उक्त बैठक में नशापान, डारन प्रथा, यातायात से संबंधित नियमों के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही मुख्य प्रलिधनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, सर्वेक्षण जगहों की पहचान, क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने, किरायेदारों की पहचान तथा पर्व त्यौहार या अन्य अवसर पर घर बंद कर अचल जाने की जानकारी संबंधित पुलिस अधिकारियों को देने जैसे बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में काफी संख्या में उपस्थित थे।

कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसानों के बीच सरगुजा बीज का किया गया वितरण

गुमला। कृषि विज्ञान केंद्र विकास भारती विश्वनगर के द्वारा वलस्टर अग्र पंक्ति प्रत्यक्ष के अंतर्गत सरगुजा प्रभेद बिरसा नाइजर वन का किसानों के बीच वितरण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री महेंद्र भगत ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से सरगुजा की खेती में कमी आई है। परंतु यह फसल कम पानी में भी अच्छी पैदावार देने में सक्षम थी। इस वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक व प्रधान डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि सरगुजा की फसल लगभग 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। साथी ही साथ इसमें लागत कम होने के कारण किसानों के लिए काफी उपयोगी है। डॉ कुमार ने बताया कि इसके बीजों की मांग विदेशों में ज्यादा है। इस कारण इसका बाजार मूल्य भी ज्यादा होता है डॉ कुमार ने बताया कि इस वर्ष कृषि विज्ञान केंद्र 250 पकड़ में किसानों के खेत पर सरगुजा की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। जिससे गुमला जिला तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अलत हि्तारी तिवारी, एन ओ राई के साथ-साथ कलवारी उरांव, लालमोहन उरांव, राजेश उरांव के साथ 25 किसानों ने भाग लिया।

मनरेगा में हो रही गड़बड़ी व घोटाले पर कार्रवाई की उपायुक से मांग

गुमला। झारखंड नवनिर्माण दल व प्रगतिशील मनरेगा मजदूर यूनियन गुमला द्वारा जिले में मनरेगा की कृष निर्माण, वृक्षारोपण, इत्यादि विभिन्न योजनाओं में मनरेगा कर्मी तथा बिचौलियों से मिली भगत कर हो रही घोटाले की जांचोपरांत कानूनी कार्रवाई की मांग गुमला उपायुक से की है। खासकर प्रगतिशील मनरेगा मजदूर यूनियन के द्वारा यह भी कहा गया है कि गुमला जिला के सुदूरवर्ती पंचायत व गांव में जहां मनरेगा मजदूर उपलब्ध है वहां भी कामज पर योजना चला कर बड़े पैमाने पर फजीर्बाद हो रहा है। इस पर जिले के उपायुक का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यूनियन ने कहा है कि मनरेगा एक्ट होने के बावजूद योजनाओं में लूट मची है और मजदूर को काम देने वाले एक्ट लूट का बारागाह बनी हुई है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहीद तेलंगा खडिया के गांव मुरगु में सिसई प्रखंड स्थित भूमिहीन गरीबों के नाम से वृक्षारोपण इत्यादि योजना स्वीकृत कर 50 लाख से भी ज्यादा रुपए की घोटाले कर ली गई है। वहीं दूसरी प्रखंड में 25 लाख की भी गबन का मामला मनरेगा की योजना के नाम पर आया है जिस पर जल्द ही कार्रवाई की मांग उपायुक से की गई है जिसकी लिखित सूचना प्रगतिशील मनरेगा मजदूर यूनियन के द्वारा गुमला जिला प्रशासन को दी गई है। यूनियन जिले के सभी प्रखंड जहां से मनरेगा मजदूरों की शिकायत मिलती है उन सभी पंचायत व गांव में यूनियन की खास टीम निरीक्षण के लिए जाएगी और गलत पाए जाने पर जांचोपरांत कार्रवाई के लिए प्रशासन को पूरे साक्ष्य के साथ मांग-पत्र दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो यूनियन मजदूरों को संगठित कर आंदोलन भी करेगी।

संस्थापक
स्व. डॉ अभय कुमार सिंह
स्वामित्व वृन्दा मीडिया
पब्लिकेशन्स
प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक, प्रकाशक
मंजू सिंह
द्वारा चित्रांदी, बोडेया रोड, रांची
(झारखंड) से मुद्रित एवं
प्रकाशित।
संपादक
अविनाश ठाकुर*
फोन : 95708-48433
फिन: -834006
e-mail
khabarmantra.city@gmail.com
R.N.J No.
JHAHIN/2013/511797

*पौआरबी एक्ट के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी। प्रकाशित खबरों से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा रांची न्यायालय में ही होगा।





रोजगार और आर्थिक विकास के लिए 2024 में लागू हो सकता है स्कूलों में ब्लू करिकुलम



कृषम पी

समुद्र के जरिये अर्थव्यवस्था को गति देने पर केंद्र सरकार के जोर के बीच विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने स्कूल-कॉलेजों में समुद्र पर केंद्रित कोर्स शुरू करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि तीन तरफ से भारत को घेर रहा समुद्र आजीविका का बहुत बड़ा साधन बन सकता है, इसलिए नई पीढ़ी को बचपन से ही उसके बारे में पढ़ाकर रोजगार के नए साधन दिए जा सकते हैं।

राजधानी में 9 दिसंबर को ह्रसाउथ एशियन ब्लू करिकुलम फॉर मॉडर्न एजुकेशन: इंडिया एंड बिम्स्टेक राउंडटेबल सम्मेलन में भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, बांग्लादेश, तिब्बत जैसे बिम्स्टेक (बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकनॉमी कोऑपरेशन) देशों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भारत के लिए समुद्र की अहमियत बताते हुए पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने की बात कही। उनका कहना था कि भारत का 95 फीसदी व्यापार समुद्र के रास्ते ही होता है और समुद्री उत्पादों से लाखों लोगों को आजीविका मिलती है। रोजगार और आर्थिक विकास के इतने बड़े साधन को बढ़ावा देने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में उसे शामिल करना फायदेमंद रहेगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार समुद्र के रास्ते अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई पहल कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023 के दौरान समुद्र पर आधारित भारत की ब्लू इकॉनमी के लिए दीर्घकालिक खाका भी पेश किया। सरकार का जोर बेशक बंदरगाह विकसित करने, जहाज बनाने, पर्यटन बढ़ाने और समुद्र के रास्ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार

को बढ़ावा देने पर है मगर इसे मुमकिन करने के लिए कम उम्र से ही लोगों को समुद्र की अहमियत बताना जरूरी है।

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी और फ्रेडरिक न्यून फाउंडेशन संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में दिल्ली सरकार के मुख्य शिक्षा सलाहकार शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार स्कूल पाठ्यक्रम में लगातार सुधार की कोशिश कर रही है, जो पिछले कई सालों से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ह्यब्लू करिकुलम तैयार करने की यह पहल वाकई सराहनीय है। ऐसा करिकुलम तैयार किया जाता है तो इसे दिल्ली में लागू करने की संभावनाएं जरूर खंगाली जाएंगी।

फ्रेडरिक न्यून फाउंडेशन के दक्षिण एशिया प्रमुख डॉ कस्टन ब्लेन ने महासागरों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए आर्थिक विकास के माध्यम तलाशने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा, समुद्र तट के 150 किमी के दायरे में 3.3 करोड़ लोगों की आबादी और 18 फीसदी आबादी 72 तटीय जिलों में होने के कारण भारत के लिए समुद्र की बड़ी अहमियत है। देश का 95 फीसदी व्यापार समुद्र के रास्ते होता है और सुरक्षा के लिहाज से भी समुद्र बहुत महत्वपूर्ण है।

डॉ क्लेन ने खास तौर पर तटीय राज्यों के युवाओं को समुद्री अर्थव्यवस्था में मौजूद व्यापक

अवसर और जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली चुनौतियां बताने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज के लाखों छात्र कल अपनी आजीविका के लिए समुद्र से जुड़े व्यवसायों पर निर्भर हो सकते हैं। इसलिए उन्हें समुद्री संसाधनों के दोहन में संवेदनशीलता बरतना भी सिखाना होगा, जो कारगर तरीके से हो सकता है।

सम्मेलन में एनसीईआरटी के शैक्षणिक सर्वेक्षण विभाग की प्रमुख डॉ इंद्राणी भादुड़ी, यूनेस्को की शिक्षा विशेषज्ञ जॉयसी पोअन, विश्व बैंक के सलाहकार संजय गुला, सेंटर फॉर एन्वायरमेंट एजुकेशन की निदेशक डॉ संस्कृति मेनन और विभिन्न शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया।

बिहार से अलग होकर भी विकास की बात जोहता झारखंड



रानी राज

बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बने 23 वर्ष से अधिक हो गये, लेकिन आज भी वे सपने अधूरे हैं जो 'झारखण्ड अलग राज्य' आंदोलन के आधार बने थे। राज्य अलग बना लेकिन आज भी रोजगार हो या पढ़ाई, यहाँ के लोगों को राज्य से बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर रोजगार के अभाव के कारण लोगों का यहाँ से पलायन

मजबूरी बन गया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए बारहवाँ के बाद बहुतायत में बच्चे दिल्ली, महाराष्ट्र या दक्षिण भारत के राज्यों में जा रहे हैं। पलायन का मुख्य कारण शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं होना एवं राज्य में रोजगार सृजन का अभाव है। साथ ही झारखंड में मजदूरी दर कम है, जबकि औद्योगिक विकास वाले राज्यों में मजदूरी दर अधिक है। अगर साल में एक बार भी श्रमिक वहां चले जाते हैं तो उनके पास अच्छी बचत हो जाती है। देश में आंतरिक पलायन के अलावा झारखंड के श्रमिक अब सऊदी अरब, मलेशिया, तर्जाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया, ईरान, कुवैत, दुबई, कजाकिस्तान

झारखंड से किए जाने वाले पलायन और दूसरे राज्यों में होने वाले पलायन में एक आधारभूत अंतर यह है कि यहां के युवक- युवतियां पलायन कर अपना भूख मिटाते हैं जबकि अन्य राज्यों से पलायन करने वाले श्रमिक अपने लिए और परिवार के लिये संसाधन जुटाते हैं।

आदि देशों में भी जा रहे हैं। झारखंड से किए जाने वाले पलायन और दूसरे राज्यों में होने वाले पलायन में एक आधारभूत अंतर यह है कि यहां के युवक-युवतियां पलायन कर अपना भूख मिटाते हैं जबकि अन्य राज्यों से पलायन करने वाले श्रमिक अपने लिए और परिवार के लिये संसाधन जुटाते हैं। झारखंड में पलायन के माध्यम में मानव तस्करी और जाँब कंसल्टेंसी/प्लेसमेंट एजेंसी की

भूमिका भी कई बार चर्चा का विषय भी बनता रहा है।झारखंड में इन तस्करी के शिकार लोगों में अधिकतर आदिवासी लड़कियां होती हैं। पलायन व मानव तस्करी विकास से जुड़े कई विरोधाभासी मुद्दों में से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। न्यूज पेपरों के आकड़ों के अनुसार झारखंड में मानव तस्करी का शिकार होने वाली बच्चियों में 90 फीसदी आदिवासी हैं। महिलाएं पलायन हो रहे

समुदाय में सबसे बड़ा हिस्सा हैं और वे लिंग आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा का भी सबसे ज्यादा शिकार होती हैं। जलवायु परिवर्तन ने भी झारखंड से पलायन को प्रेरित किया है। वनों की कटाई और खेतों की घटती उत्पादकता ने यहाँ के निवासियों को दिहाड़ी मजदुर बनने को मजबूर किया है। लोग भूख की आग में आसानी से मानव तस्करी के चपेट में आ जा रहे हैं। मानव तस्करी का एक प्रमुख उद्देश्य महानगरों में इन आदिवासी लड़कियों से घरेलू काम करवाना होता है। जहाँ इनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है।

झारखंड से पलायन और मानव तस्करी की समस्या कोई आर्थिक नहीं बल्कि आर्थिक -

सामाजिक और प्रशासनिक समस्या है। रोजगार सृजन के साथ प्रशासनिक स्तर पर गहन जाँच और निगरानी ही मानव तस्करी को रोक सकती है। कई बार तो आम लोग शिकायत तक नहीं कर पाते हैं और चुपचाप शोषण का शिकार हो जाते हैं। समाज को भी सशक्त एवं जागृत रहने की आवश्यकता है ताकि मानव तस्करी के एजेंट गावों में घुस न सके और न ही कोई बहला- फुसला कर उन्हें शहरों में ले जा सके। समाज को उस आदिम व्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता है जिसमें सभी एक - दूसरे की सहायता कर खुशहाल रहते हैं।

(ऑडिट ऑफिसर, रजौली, नवादा, बिहार)

खुले खनन से बेहतर है भूमिगत कोयला खनन



भूमिगत खनन के बहुत अधिक फायदे हैं। पर्यावरण के स्तर पर भी यह अधिक स्वच्छ तरीका है। दूसरा, इसके लिए अधिक भूमि खुदाई की जरूरत नहीं होती और भूमि अधिग्रहण के झंझट से बचने के साथ-साथ वनों की रक्षा भी होती है। इस तरीके को अपनाकर कृषि भूमि को बचाया जा सकता है।

सबसे बड़ी बात, यह समाज अनुकूल भी है, क्योंकि इसमें लोगों को सामूहिक विस्थापन का सामना नहीं करना पड़ता और पुनर्वास एवं मुआवजे जैसी प्रक्रियाओं में नहीं जाना पड़ता। साथ ही रोजी-रोटी के पारंपरिक स्रोत भी खत्म नहीं होते। विशेष यह कि भूमिगत खनन से मिलने वाला कोयला बेहतर गुणवत्ता वाला होता है और इससे उच्च श्रेणी के कोयले का आयात कम करने में मदद मिलती है।

भारत में मुख्यतः खुली विधि से कोयला खनन होता है। वर्ष 2022 में पूरी दुनिया में कुल 8.5

अरब टन कोयले का उत्पादन हुआ। इसमें भूमिगत विधि से निकाले गए कोयले की मात्रा लगभग 55 फीसदी थी। इसके उलट, भारत के कोयला उत्पादन में भूमिगत की मात्रा केवल चार फीसदी ही रही। लेकिन, हमेशा से ऐसी स्थिति नहीं रही है। वर्ष 1975 में देश की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की स्थापना के बाद पहले दशक में भूमिगत विधि से अधिक उत्पादन हुआ, बजाय कि खुली पद्धति के। वित्त वर्ष 1985 में पहली बार खुली विधि का पलड़ा भारी हो गया जब इससे उत्पादित कोयले की मात्रा 7.03 करोड़ टन हो गई और भूमिगत विधि से उत्पादित कोयले की मात्रा 6.03 करोड़ टन रह गई।

इसके बाद यह खाई पाटी नहीं जा सकी। बीते 38 वर्षों में सीआईएल का खुली विधि से कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2023 की समाप्ति तक 9.64 गुना

उत्पादन प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने पर यह संभव हो सकता है। घरेलू विनिर्माण और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए खनन उपकरणों का मानकीकरण भी इसमें खासी मदद कर सकता है। भूमिगत खनन विधि को जो चीजें व्यावहारिक बनाती हैं, उनमें कुशल एवं प्रशिक्षित ऑपरेटर, ठेकेदारों को आउटसोर्सिंग, कुशल खदान डेवलपर और कंत्रित एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली प्रौद्योगिकी की उपलब्धता शामिल है। इसमें भारतीय हालात के अनुकूल लगातार खनन करने वाले खनिक, मौजूदा उपलब्ध बुनियादी ढांचे के जरिये कम लागत पर निकासी के लिए पंच एंटी विधि, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास प्रक्रियाओं जैसे मुद्दों से छुटकारा दिलाने उच्च तकनीक से लैस वॉल मशीनों भी जोड़ी जा सकती हैं। साथ-साथ पेस्ट फिल तकनीक भी लाभप्रद होती है।

भूमिगत खनन विधि में खाली हुई जगह को भरने के लिए पारंपरिक रेत के बजाय फ्लाइ ऐश का इस्तेमाल किया जाता है। भूमिगत खनन विधि धरातल पर किसी प्रकार की अड़चन पैदा किए बिना चलती है।

खनन से पैदा हुए खड्डों में राख भराव का काम भी बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाता है। खुली विधि और भूमिगत विधि से 10 लाख टन कोयला उत्पादन में पीएम10 के कंटेनर का तुलनात्मक आकलन सीआईएल की परामर्शदाता कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट और यूनाइटेड स्टेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने किया था।

उत्पादन प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने पर यह संभव हो सकता है। घरेलू विनिर्माण और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए खनन उपकरणों का मानकीकरण भी इसमें खासी मदद कर सकता है। भूमिगत खनन विधि को जो चीजें व्यावहारिक बनाती हैं, उनमें कुशल एवं प्रशिक्षित ऑपरेटर, ठेकेदारों को आउटसोर्सिंग, कुशल खदान डेवलपर और कंत्रित एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली प्रौद्योगिकी की उपलब्धता शामिल है। इसमें भारतीय हालात के अनुकूल लगातार खनन करने वाले खनिक, मौजूदा उपलब्ध बुनियादी ढांचे के जरिये कम लागत पर निकासी के लिए पंच एंटी विधि, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास प्रक्रियाओं जैसे मुद्दों से छुटकारा दिलाने उच्च तकनीक से लैस वॉल मशीनों भी जोड़ी जा सकती हैं। साथ-साथ पेस्ट फिल तकनीक भी लाभप्रद होती है।

भूमिगत खनन विधि में खाली हुई जगह को भरने के लिए पारंपरिक रेत के बजाय फ्लाइ ऐश का इस्तेमाल किया जाता है। भूमिगत खनन विधि धरातल पर किसी प्रकार की अड़चन पैदा किए बिना चलती है।

खनन से पैदा हुए खड्डों में राख भराव का काम भी बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाता है। खुली विधि और भूमिगत विधि से 10 लाख टन कोयला उत्पादन में पीएम10 के कंटेनर का तुलनात्मक आकलन सीआईएल की परामर्शदाता कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट और यूनाइटेड स्टेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने किया था।

उत्तर प्रदेश: कैसे बना देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

शिवेश प्रताप सिंह

योगी ने कभी बीमारू माने जाने वाले उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में अग्रणी स्थान पर ला खड़ा किया है। विश्लेषण मंच एसओआईसी के अनुसार संसेक्स तथा क्रैडिट लियोनिस सिक्वोरिटीज एशिया आधारित रिपोर्ट्स के हिसाब से देश की जीडीपी में हिस्सेदारी के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। देश की कुल जीडीपी में महाराष्ट्र 15.7 प्रतिशत जीडीपी योगदान के साथ पहले पायदान पर है तो वहीं उत्तर प्रदेश 9.2 प्रतिशत जीडीपी के साथ दूसरे स्थान पर है। बीते कुछ समय से तमिलनाडु से काटे की टक्कर में उत्तर प्रदेश को अब बढ़त मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा है। योगी का उत्तरप्रदेश कैसे आज से सात साल पहले असंभव से लगने वाले इस लक्ष्य को हासिल कर आगे बढ़ते हुए भारत के जीडीपी योगदान में प्रथम स्थान हासिल करने हेतु निरंतर प्रगतिशील है। किसी भी प्रदेश के लिए ऐसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मात्र घरेलू बाजार की निर्भरता को खत्म कर अपने निर्यात से पूरी दुनिया में व्यापारिक पैठ बनाने की आवश्यकता होती है। घरेलू बाजारों की मांग एवं क्रय शक्ति सीमित होती है जो एक सीमित राजस्व ही पैदा करने में सक्षम होती है। एक्सपोर्ट के माध्यम से एक विशालकाय बाजार के साथ अच्छे लाभ एवं राजस्व प्राप्ति का रास्ता भी खुलता है।

उत्तर प्रदेश का निर्यात पिछले छह वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के डेटा के अनुसार 2016-17 में प्रदेश का निर्यात 84,000 करोड़ रुपये का था जो 2022-23 में बढ़कर दोगुने से अधिक यानी 1,74,000 करोड़ रुपये का हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा दो लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यही अनुसूनाई सिद्ध करती है कि कभी बीमारू राज्य का टैग लेकर घूमने वाला उत्तर प्रदेश योगी सरकार की क्रांतिकारी नीतियों के कारण भारत का नया एक्सपोर्ट हब बनने जा रहा है।

उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल उत्पादन करने वाला प्रदेश है तथा राष्ट्रीय उत्पादन में 13.24 प्रतिशत का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश में लगभग ढाई लाख हैंडलूम बुनकर तथा चार लाख 21 हजार पावरलूम बुनकर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में निर्यातको और बढ़ाना चाहती है साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि इस उद्योग से जुड़ा हुआ अंतिम 1,74,000 करोड़ रुपये का हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा दो लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यही अनुसूनाई सिद्ध करती है कि कभी बीमारू राज्य का टैग लेकर घूमने वाला उत्तर प्रदेश योगी सरकार की क्रांतिकारी नीतियों के कारण भारत का नया एक्सपोर्ट हब बनने जा रहा है।

उत्तर प्रदेश का 60 प्रतिशत निर्यात दुनिया के 10 देशों वियतनाम, नीदरलैंड, फ्रांस, चीन, मिश्र, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम तथा जर्मनी को होता है। 2022-23 में सबसे अधिक निर्यात 32,800 करोड़ अमेरिका को, 14,300 करोड़ संयुक्त अरब अमीरात को तथा लगभग दस-दस हजार करोड़ जर्मनी एवं यूनाइटेड किंगडम को हुआ। उत्तर प्रदेश से वर्तमान में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, दूरसंचार उपकरण, कंटैन, कृत्रिम फाइबर आदि के साथ गेहूं, चावल, कालीन एवं हस्तशिल्प भी महत्वपूर्ण निर्यात सामग्री है। परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं उत्तर प्रदेश के संपूर्ण निर्यात का 18.9 प्रतिशत है। इसके बाद कपड़ा उद्योग 9.5 प्रतिशत का योगदान करता है।

एक्सपोर्ट एक्सीलेंस वाले शहरों में ऐसे शहरों को चयनित किया जाता है जिसकी उत्पादन सीमा 750 करोड़ रुपये से अधिक की हो और निर्यात क्षमता भविष्योन्मुख हो। आज भारत भर में केंद्र सरकार के द्वारा चिह्नित किए गए 43 सेंटर आफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस हैं। इनमें 12 सेंटर अकेले उत्तर प्रदेश में हैं जो इस प्रदेश के निर्यात सामर्थ्य को बनाते हैं। उत्तर प्रदेश चारों तरफ से स्थलीय एवं पहाड़ी सीमाओं के बीच स्थित है।सामान्यतः या निर्यात प्रोत्साहन हेतु समुद्री सीमा किसी भी प्रदेश को बेहद महत्वपूर्ण बना देती है लेकिन उत्तर प्रदेश के पास कोई समुद्री सीमा न होते हुए भी 12 सेंटर आफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की मौजूदगी प्रदेश सरकार के विकास के संकल्प को स्वयं बताती है।

जलमार्ग से सस्ते यातायात

का लाभ तटीय प्रदेशों को मिलता है लेकिन इस चुनौती के समाधान के लिए भी प्रदेश की योगी सरकार ने गंभीरता से कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश के उद्योगों को जलमार्ग से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। समुद्री बंदरगाहों की अनुपस्थिति में निर्यात की सुगमता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के भीतर शुष्क बंदरगाहों का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा करने के लिए कार्यरत है। इसी क्रम में योगी सरकार ने सिंगापुर के स्टार कंसोर्सियम तथा संयुक्त अरब अमीरात के सराफ ग्रुपके साथ-साथ हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड व अमेरिका की दो कंपनियों मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तथा बेस्ट बेटकिंग ग्रुप के साथ एमओयू साइन किया है।

वर्तमान में मुरादाबाद रेल लिंकड जाईंट डोमेस्टिक एक्सप्रेट मिंनल, रेल लिंकड प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल तथा कानपुर व दादरी में शुष्क बंदरगाह सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। जलमार्ग के लिए वाराणसी से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक गलराज मार्ग संख्या एकप्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों के संरक्षण एवं संवर्धन के द्वारा निर्यात को बढ़ाने पर है। इन पारंपरिक उद्योगों में भी दो ऐसे क्षेत्र टेक्सटाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के पास एक बहुत बड़ा अवसर है।

उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल उत्पादन करने वाला प्रदेश है तथा राष्ट्रीय उत्पादन में 13.24 प्रतिशत का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश में लगभग ढाई लाख हैंडलूम बुनकर तथा चार लाख 21 हजार पावरलूम बुनकर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में निर्यातको और बढ़ाना चाहती है साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि इस उद्योग से जुड़ा हुआ अंतिम 1,74,000 करोड़ रुपये का हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा दो लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यही अनुसूनाई सिद्ध करती है कि कभी बीमारू राज्य का टैग लेकर घूमने वाला उत्तर प्रदेश योगी सरकार की क्रांतिकारी नीतियों के कारण भारत का नया एक्सपोर्ट हब बनने जा रहा है।

उत्तर प्रदेश का 60 प्रतिशत निर्यात दुनिया के 10 देशों वियतनाम, नीदरलैंड, फ्रांस, चीन, मिश्र, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम तथा जर्मनी को होता है। 2022-23 में सबसे अधिक निर्यात 32,800 करोड़ अमेरिका को, 14,300 करोड़ संयुक्त अरब अमीरात को तथा लगभग दस-दस हजार करोड़ जर्मनी एवं यूनाइटेड किंगडम को हुआ। उत्तर प्रदेश से वर्तमान में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, दूरसंचार उपकरण, कंटैन, कृत्रिम फाइबर आदि के साथ गेहूं, चावल, कालीन एवं हस्तशिल्प भी महत्वपूर्ण निर्यात सामग्री है। परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं उत्तर प्रदेश के संपूर्ण निर्यात का 18.9 प्रतिशत है। इसके बाद कपड़ा उद्योग 9.5 प्रतिशत का योगदान करता है।

एक्सपोर्ट एक्सीलेंस वाले शहरों में ऐसे शहरों को चयनित किया जाता है जिसकी उत्पादन सीमा 750 करोड़ रुपये से अधिक की हो और निर्यात क्षमता भविष्योन्मुख हो। आज भारत भर में केंद्र सरकार के द्वारा चिह्नित किए गए 43 सेंटर आफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस हैं। इनमें 12 सेंटर अकेले उत्तर प्रदेश में हैं जो इस प्रदेश के निर्यात सामर्थ्य को बनाते हैं। उत्तर प्रदेश चारों तरफ से स्थलीय एवं पहाड़ी सीमाओं के बीच स्थित है।सामान्यतः या निर्यात प्रोत्साहन हेतु समुद्री सीमा किसी भी प्रदेश को बेहद महत्वपूर्ण बना देती है लेकिन उत्तर प्रदेश के पास कोई समुद्री सीमा न होते हुए भी 12 सेंटर आफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की मौजूदगी प्रदेश सरकार के विकास के संकल्प को स्वयं बताती है।

जलमार्ग से सस्ते यातायात



